एसपी बka ग M+ से पहले जे.

जमालौ के नूर मोहम्मद पुत्र
@ जमालुद्दीन-फीट^डब्ल्यूआर

बनाम

एस टैट ईओ एफ 11 आर्य एनए- *उत्तर दें टी*

1992 का सीआरए नंबर 1-389-एसबी

अप्रैल 09, 2013

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - एस.एस. 42, 50, 55, 57 - अपीलकर्ता के दाहिने हाथ में 4 किलोग्राम अफ़ीम थी - अपीलकर्ता को धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल के लिए आरआई और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 42, 50, 55 और 57 के गैर-अनुपालन के सही निष्कर्ष नहीं निकालने में गलती की - एकमात्र स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया - अपील खारिज कर दी गई।

मैंने 'अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2010) 3 सर्वोच्च न्यायालय मामले, 746' में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 'मदन लाल बनाम आईएलपी राज्य' पर भरोसा करते हुए रखा। (2003) 7 एससीसी, 465' ने माना कि अधिनियम की धारा 50 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होता है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। अजमेर सिंह के मामले (सुप्रा) में, मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी राज्य आईआईपी वी. पवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350 पर भरोसा किया, जिसमें, यह माना गया था कि एक बैग, ब्रीफकेस या ऐसा कोई लेख या कंटेनर आदि को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता।

(पैरा 24)

इसके अलावा, यह माना गया कि, उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान केवल अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होंगे, न कि कुछ सामान जैसे बैग, वस्तु या कंटेनर आदि की, जो (अभियुक्त)) ले जा सकता है।

(पैरा 25)

आगे माना गया कि इस मामले में अफ़ीम की बरामदगी किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी से नहीं की गई थी। वह केवल अपीलकर्ता द्वारा अपने दाहिने हाथ में लिए गए बैग से बनाया गया था। संदेह के आधार पर, अपीलकर्ता को पीडब्लू-4 द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसे संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेने का पूरा अधिकार था। मैं राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना, अपीलकर्ता द्वारा अपने दाहिने हाथ में ले जाए जा रहे बैग को बरामद करने में पूरी तरह से सक्षम था।

(पैरा 29)

आगे कहा गया, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तो उसकी आगे की हिरासत अमान्य या गैरकानूनी हो सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी प्रारंभिक गिरफ्तारी ही अवैध हो जाती है। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के साक्ष्यों में यह आया है कि अफीम की बरामदगी में परिवर्तन करते हुए, गिरफ्तारी के आधार प्रतिवादी को सूचित किए गए थे। अत: यह नहीं माना जा सकता कि जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 52 का अनुपालन नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क, योग्यता से रहित होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(पैरा 32)

आगे कहा गया, कि 'रूप सिंह बनाम' के मामले में। पंजाब राज्य 1996 (1) आरसीआर (सीआरएल) 146' इस न्यायालय द्वारा तय किया गया कि स्वतंत्र गवाह को जीत लिया गया और छोड़ दिया गया; मामला सरकारी गवाहों पर आधारित था; इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि पुलिस अधिकारी दुर्भावनापूर्ण था और मामले को झूठा फंसाने में रुचि रखता था; पुलिस अधिकारियों की गवाही को उनकी विस्तृत जिरह में खारिज नहीं किया जा सका। इस फैसले के मद्देनजर, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता।

(पैरा 38)

आगे कहा गया कि विश्लेषण के लिए एफएसएल को नमूना भेजने में 11 दिनों की देरी हुई। यह देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है, क्योंकि उस देरी का उपयोग नमूना पार्सल और केस संपत्ति को गढ़ने के लिए नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि मामले की संपत्ति पीडब्लू/1, पीडब्लू/2, पीडब्लू/4 और पीडब्लू/5 के कब्जे में रही। जिरह के दौरान उनकी गवाही को खंडित नहीं किया जा सका।

(पैरा 41)

अशीत मलिक, अधिवक्ता,/या *अपीलकर्ता।*

जी.एस. संधू, एएक्यू *हरियाणजेबीआर प्रतिवादी।*

एसपी बंगारू, जे.

(1) अभियोजन की आसानी यह है कि 17.09.1989 को, महा सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस स्टेशन सिटी पानीपत, दोपहर लगभग 3.00 बजे अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ, जीटी के किनारे स्थित आदर्श उद्योग फैक्ट्री पानीपत के पास मौजूद थे। रोड, जहां रमेश चंद पीडब्लू पुलिस पार्टी से मिले और पुलिस पार्टी में शामिल हो गए। इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता को एक महिला के साथ जीटी के किनारे पैदल आते देखा गया। दिल्ली की ओर से अपने दाहिने हाथ में एक बैग Lx.PI लेकर आ रहा था, जिसने पुलिस पार्टी को देखकर अपनी दिशा पूर्व की ओर बदल ली, जिससे सहायक उप निरीक्षक महा सिंह के मन में संदेह पैदा हो गया, जिसने अपीलकर्ता और मुन्नी बाई को पकड़ लिया और बताया वे चाहते थे कि उनकी तलाशी आराम से की जाए और किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में भी की जा सके। अपीलकर्ता और मुन्नी बाई दोनों ने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के बिना तत्कालीन एएसआई (सुप्रा) माबा सिंह द्वारा तलाशी लेने का विकल्प चुना और उन्होंने अपीलकर्ता की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप एक बैग एलएक्स.पी 1 मिला जिसमें 4 किलोग्राम अफीम लिपटी हुई थी। एक पॉलिथीन पेपर में. अपीलकर्ता इसके लिए कोई परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। थोक अफीम में से नमूने के तौर पर 200 ग्राम ओओपिउरन निकाला गया, जिसे एक छोटे टिन के डिब्बे में डाल दिया गया, जबकि शेष अफीम को दूसरे टिन के डिब्बे में डाल दिया गया।

(2) दोनों बक्सों को पार्सल में बनाया गया था, जिन्हें तत्कालीन एएसआई महा सिंह ने अपनी सील छाप 'एमएस' के साथ सील कर दिया था। बैग Fx.Pl सहित नकद संपत्ति को vidc रिकवरी मेमो Lx.PA के साथ जब्त कर लिया गया था, जिसे धन रण द्वारा सत्यापित किया गया था। मैं आईसी और रमेश चंद सरकारी गवाह। उपयोग के बाद सील को बाद वाले को सौंप दिया गया। बाद में, रुका एलएक्स.पीबी को तत्कालीन एएसआई महा सिंह द्वारा पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत भेजा गया, जहां तत्कालीन एसआई रामेश्वर दत्त द्वारा औपचारिक एफआईआर एलएक्स.पीबी/1 दर्ज की गई थी। बाद में, तत्कालीन एएसआई महा सिंह ने रफ साइट प्लान एलएक्स तैयार किया। अफीम की बरामदगी के स्थान की पीसीसी की और अपीलकर्ता को उचित आधार बताने के बाद गिरफ्तार कर लिया।

(3) पुलिस स्टेशन लौटने पर, आसान संपत्ति ओम प्रकाश प्रथम आईसी के पास जमा कर दी गई। मुन्नी बाई के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर जांच की गई। पुलिस स्टेशन लौटने पर, अपीलकर्ता और आसानी संपत्ति को केदार सिंह राठी एसआई आईओ के सामने पेश किया गया, जिन्होंने सभी संबंधित तथ्यों से तथ्यों को सत्यापित किया और मामले की संपत्ति पर अपना स्वयं का मुहर वाला पत्र 'केएसआर' चिपका दिया। बाद में। तत्कालीन एएसआई महा सिंह ने ईज संपत्ति को ओम प्रकाश प्रथम आईसी के पास जमा कर दिया, जिन्होंने इस ईज में नमूना पार्सल भेजा पवन कुमार कांस्टेबल के माध्यम से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन और पूर्व वीडियो रिपोर्ट एक्स.पीडी ने नमूना पार्सल की सामग्री को अफीम की घोषित किया।

(4) जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने अपीलकर्ता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी-संक्षेप में) की धारा 173 के तहत विद्वान इलाक़ा मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट स्थापित की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(5) पुलिस रिपोर्ट की प्रस्तुति पर, सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां विद्वान इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता को प्रदान की गईं, जिन्होंने बाद में मामले को सत्र न्यायालय में भेज दिया, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट में भेजा गया, जहां आरोप लगाया गया। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता ने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया। परिणामस्वरूप, अभियोजन साक्ष्य तलब किया गया।

(6) मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से पूछताछ की, जिनकी गवाही इस प्रकार है: -

(7) पीडब्लू-1 ओम प्रकाश एचसी नंबर 160 ने गवाही दी कि 17.09.1989 को, वह पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत में तैनात थे, उस दिन, महा सिंह एएस मैंने 'केएसआर' अंकित मुहरों के साथ विधिवत रूप से स्केल किए गए अफीम के दो स्केल्ड पार्सल जमा किए थे। और 'एमएस' और उन्होंने पवन कुमार कांस्टेबल नंबर 1122 के माध्यम से विश्लेषण के लिए इस मामले के अफीम का नमूना पार्सल 1 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन को भेजा और बाद वाले ने मामले की संपत्ति को पूर्व के पास जमा कर दिया और जब तक, मामले की संपत्ति उसके कब्जे में रहा, किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की।

(8) पीडब्लू-2 पवन कुमार कांस्टेबल ने गवाही दी कि 28.09.1989 को, वह पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत में तैनात था और उस दिन, ओम प्रकाश एचसी (पीडब्लू-1) ने उसे सीलबंद अफीम का एक सीलबंद पार्सल सौंपा था। 'केएसआर' और 'एमएस' को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन के कार्यालय में जमा करने के लिए और उसने सीलबंद पार्सल को उसी दिन प्रयोगशाला (सुप्रा) में जमा कर दिया और पुलिस स्टेशन लौटने पर, उसने उसे सौंप दिया। ओम प्रकाश एचसी (पीडब्लू-1) को सड़क प्रमाण पत्र। 1 यानी आगे गवाही दी कि, जब तक स्केल किया हुआ पार्सल उसके कब्जे में रहा, तब तक किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की।

(9) पीडब्लू-3 धन राज एचसी ने गवाही दी कि 17.09.1989 को, वह पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत में तैनात थे और उस दिन, वह महा सिंह एएसआई और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ जीटी रोड एनसीआरआदर्श फैक्ट्री, पानीपत में मौजूद थे, जहां, रमेश चंदर पीडब्ल्यू उनसे मिले और पुलिस पार्टी में शामिल हो गए और अपीलकर्ता मुन्नी बाई के साथ जीटी पर पैदल आए। सड़क, दिल्ली की ओर से बैग एक्स.पी.आई. ले जाते हुए। पुलिस पार्टी को देखकर, दोनों ने ढलाई की ओर अपनी दिशा

बदल दी, जिससे महा सिंह एएसआई के मन में संदेह पैदा हुआ और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें बताया, कि वे बीएससीस्कारचडी की ओर जा रहे हैं। और यदि वे चाहें, तो इसे राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया जा सकता है। मैंने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता और मुन्नी बाई ने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के बिना तलाशी लेने का विकल्प चुना और बाद में, महा सिंह एएसआई ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत तलाशी दी और उसके बाद, उन्होंने अपीलकर्ता की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 4 किलोग्राम अफ़ीम बरामद हुई। और अपीलकर्ता उस अफ़ीम को अपने कब्जे में रखने के लिए कोई परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा सका। उन्होंने आगे गवाही दी कि 200 ग्राम अफ़ीम को नमूने के तौर पर अलग कर लिया गया था। नमूना अफ़ीम और शेष अफ़ीम दोनों को दो अलग-अलग पार्सल में बनाया गया था, जिन्हें 'एमएस' छाप वाली सील के साथ सील कर दिया गया था और उपयोग के बाद सील को रमेश चंद पीडब्ल्यू को सौंप दिया गया था। बैग Ex.Pl, स्केल्ड पार्सल Ex.P2 और नमूना पार्सल को vidc मेमो Ex.PA जब्त कर लिया गया, जिसे उनके और रमेश चंद पीडब्लू द्वारा सत्यापित किया गया था और उनका बयान मौके पर दर्ज किया गया था।

(10) पीडब्लू-4 महा सिंह, तत्कालीन एएसआई ने भी गवाही दी कि 7.09.1989 को वह पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपा में तैनात थे, उस दिन वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ जीटी पर मौजूद थे। रोड एनसीआरआदर्श उद्योग फैक्ट्री, पानीपत, एनईएल कॉलोनी के पास स्थित है, जहां रमेश चंद पीडब्लू उनसे मिले और पुलिस पार्टी में शामिल हो गए। अपराह्न लगभग 3.00 बजे अपीलकर्ता को एक महिला के साथ जीटी पर पैदल दिल्ली की ओर से आते देखा गया। सड़क पर, अपने दाहिने हाथ में एक बैग Ex.Pl ले जा रहा था और पुलिस पार्टी को देखकर, अपीलकर्ता और मुन्नी बाई ने कास्ट की ओर अपनी दिशा बदल दी और इससे संदेह पैदा हुआ और उसने दोनों को पकड़ लिया और उनसे कहा कि उनकी तलाशी ली जानी है और यदि वे इतना वांछित, कि इसे किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष आयोजित किया जा सके। मैंने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता और मुन्नी बाई ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद, कानून के अनुसार। उन्होंने आरोपी की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा ले जाए जा रहे बैग एक्स.पीएल से कागज में लपेटी हुई 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जो उसे रखने के लिए कोई परमिट पेश नहीं कर सका।

(11) उन्होंने आगे गवाही दी कि 200 ग्राम अफीम को नमूने के रूप में अलग किया गया था और एक छोटे टिन के बक्से में रखा गया था, जबकि शेष अफीम को दूसरे टिन के बक्से में रखा गया था और दोनों बक्सों को उनकी मुहर छाप 'एमएस' और बैग Ex.Pl के साथ सील कर दिया गया था। शेष अफीम Ex.P2 के पार्सल और नमूना पार्सल को मेमो Ex.PA के माध्यम से जब्त कर लिया गया, जिसे धन रान IIC (PW-3) द्वारा सत्यापित किया गया था और उपयोग के बाद सील करके रमेश चंद PW को सौंप दिया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि बाद में, उन्होंने रुका एक्स.पीबी को पुलिस स्टेशन भेजा, जहां रमेश वार दत्त एसआई द्वारा औपचारिक एफआईआर एक्स.पीबी/1 दर्ज की गई और बाद में, उन्होंने रफ साइट प्लान एक्स तैयार किया। अफीम की बरामदगी वाले स्थान की पीसी कर गवाहों के

बयान दर्ज किये तथा अपीलार्थी को गिरफ्तारी का आधार बताकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

(12) मैंने आगे गवाही दी कि घटनास्थल पर जांच के बाद, वह अपीलकर्ता और मुन्नी बाई को दो मामलों में केस संपत्ति के साथ पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें तत्कालीन एसआई आईओ केदार सिंह राठी इंस्पेक्टर के सामने पेश किया, जिन्होंने सभी तथ्यों की पुष्टि की। चोर आया और उसने पार्सलों पर 'केएसआर' छाप वाली अपनी सील लगा दी और बाद में, उसने (पी डब्लू-4) ने केस संपत्ति को एमआई आईसी के पास जमा कर दिया और बाद में, सीलबंद नमूना पार्सल को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन और बाद में भेज दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व पीडी ने नमूना पार्सल की सामग्री को अफ़ीम का बताया। इस गवाह को उसके बयान के दौरान बैग Ex.Pl और सीलबंद पार्सल Ex.P2 दिखाया गया था।

(13) पीडब्लू-5 रमेश चंद ने गवाही दी कि उनकी उपस्थिति में अपीलकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इस गवाह को प्रतिवादी/अभियोजन पक्ष के प्रति शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी/अभियोजन पक्ष के विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई थी।

पीडब्लू-6 केदार सिंह राठी, तत्कालीन पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत, ने गवाही दी कि 17.09.1989 को, महा सिंह एएसआई ने अपीलकर्ता को केस संपत्ति और पीडब्लू के साथ उनके सामने पेश किया था और उन्होंने मामले की जांच का सत्यापन किया था। अपीलकर्ता और अन्य सभी से और मामले की संपत्ति पर 'केएसआर' छाप वाली अपनी मुहर लगाई थी, जिसे बाद में मुहरों के साथ संबंधित एमएचसी के पास जमा कर दिया गया था। इस गवाह के बयान के दौरान बैग एक्स.पीएल और टिन बॉक्स जिसमें अफीम एक्स.पी2 था, पेश किया गया।

अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के बाद, अपीलकर्ता से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया और इस मामले में झूठे आरोप लगाए।

(14) अपीलकर्ता ने अपना स्वयं का संस्करण दिया कि उसे धन राज एचसी (पीडब्लू -3) ने बस स्टैंड, पानीपत से पकड़ा था और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

(15) अपीलकर्ता को बचाव में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने बचाव में किसी भी गवाह की जांच किए बिना इसे बंद कर दिया।

(16) दोनों पक्षों को सुनने के साथ-साथ, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और दस्तावेजों का

अवलोकन करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 1991 के सत्र आसानी संख्या 60 में पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश पर आपत्ति जताई, जो कि ईएफआर नंबर 794 दिनांक 17.09 से निकला है। .1989, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत, पुलिस स्टेशन सिटी, पानीपत ने अपीलकर्ता को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साल और रुपये का जुर्माना देना होगा। 1,00,000/- और इसका भुगतान न करने पर दो वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इससे व्यथित, अपीलकर्ता, इस अपील को स्वीकार करने और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध से उसे बरी करने की प्रार्थना के साथ आया है, जहां, उस पर विद्वत् परीक्षण द्वारा आरोप लगाया गया था। अदालत।

(17) अपीलकर्ता के वकील और विद्वान सहायक अधिवक्ता (जेसीसीआरएल, प्रतिवादी के लिए 1 लारियाना) को सुना गया और उनकी सहायता से विद्वान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

(18) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपेक्षित निष्पक्षता के साथ फ़्लिक सबूतों की जांच नहीं की, जिसने अभियोजन पक्ष की स्पष्ट कमजोरी पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी तर्क दिया है कि उन्हें पता चला है कि ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 50, 82, 55 और 57 के गैर-अनुपालन के बारे में सही निष्कर्ष न निकालकर गलती की है।

(19) 1.अपीलकर्ता के लिए अर्जित वकील ने यह भी तर्क दिया कि ईज़ की जांच में एकमात्र स्वतंत्र गवाह ने पीडब्लू 5 के रूप में पेश होने के दौरान ईज़ का समर्थन नहीं किया और इसलिए, उसकी गवाही को ध्यान में रखते हुए,

अन्य अभियोजन गवाहों की गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए था और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था। [1]

(20) दूसरी ओर, आई लारियाना राज्य के विद्वान सहायक महाधिवक्ता/प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है जिसे बरकरार रखा और पुष्टि की जा सके।

(21) सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या इस सहजता में अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन करना आवश्यक था। अधिनियम की धारा 50 को अंडरसीआर के रूप में पढ़ा जाता है: -

(50) शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी-

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा

43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना किसी भी निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा। धारा 42 में उल्लिखित विभागों या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो (वह अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सके।

(3) 'एफसीसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके सामने ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, लेकिन अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए। .

(4) किसी महिला को छोड़कर किसी अन्य द्वारा किसी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी

(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि तलाशी के लिए व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, जब तक कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के पास कोई मादक दवा या मनःप्रभावी पदार्थ न हो। , या नियंत्रित पदार्थ या लेख या दस्तावेज़, वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए अनुसार व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

(6) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के लिए कारण रिकॉर्ड करेगा जिसके लिए ऐसी तलाशी आवश्यक हो गई है और बहत्तर घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेजेगा।]

(23) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जब अधिकार प्राप्त अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो यदि आवश्यक हो तो वह उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। यह देखा जाना चाहिए कि अपीलकर्ता से अफीम की बरामदगी उसकी व्यक्तिगत तलाशी से नहीं की गई थी, बल्कि उसके दाहिने हाथ में लिए गए बैग से की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा अपने दाहिने हाथ में ले जाया जा रहा यह बैग जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू 4) और पुलिस दल के अन्य सदस्यों को दिखाई दे रहा था।

(24) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***अजमेर सिंह*** बनाम ***हरियाणा राज्य (1) में मदन लाल*** बनाम ***आईएलपी राज्य (2) पर*** भरोसा करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 50

को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल आसानी से लागू होता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज. इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। **अजमेर सिंह की सहजता (सुप्रा)** में , भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***आईएलआर*** बनाम ***पवन कुमार (3) के राज्य*** पर भी भरोसा किया , जिसमें यह माना गया कि एक बैग, ब्रीफकेस या ऐसा कोई लेख या कंटेनर इत्यादि। किसी भी परिस्थिति में इसे मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता। 'इली को एक अलग नाम दिया गया है और उसे इस तरह पहचाना जा सकता है। उन्हें दूर-दूर तक किसी इंसान के शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह अलग-अलग आकार की कितनी भी वस्तुएं जैसे बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन बॉक्स, थैला, झोला, गठरी, होल्डाल, कार्टन आदि ले जा सकता है। आयाम या वजन. हालाँकि, उन्हें ले जाने या साथ ले जाने में कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से अर्जित करना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा। सामान्य बोलचाल में, यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति एक विशेष वस्तु ले जा रहा है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि इसे कैसे अर्जित किया गया है जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर, आदि। इसलिए, इन वस्तुओं को के दायरे में समाप्त करना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 50 में 'व्यक्ति' शब्द आता है ।

(1) (2010)3 एससीसी 746
(2) (2003)7 465 देखें
(3) (2005) 4 देखें 350

(25) **उपरोक्त** निर्णयों के मद्देनजर , अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान केवल आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी में आसानी के लिए लागू होंगे, न कि कुछ सामान जैसे बैग, वस्तु या कंटेनर आदि की, जो (आरोपी) ले जा सकता है।

(26) **उपरोक्त** निर्णयों के इस दृष्टिकोण में , अधिनियम की धारा 50 का मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा ले जाए जा रहे एक बैग से अफीम बरामद की गई थी, जो स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपीलकर्ता को तब गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने दाहिने हाथ में अफीम से भरा बैग ले जा रहा था। इस प्रकार, PW4, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना अपीलकर्ता से अफीम की वसूली कर सकता है। इसलिए, इस मामले में अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था, जो कि अपीलकर्ता के व्यक्ति से आसानी से अफीम बरामद होने की स्थिति में किया जाना आवश्यक होता, यदि उसने तस्करी/अफीम को छुपाया होता। उसके कपड़ों में या उसके कपड़ों की जेबों में। अत: अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में उठाया गया तर्क निरस्त किया जाता है।

(27) अब देखना यह है कि इस मामले में एक्ट की धारा 42 का पालन हुआ है या नहीं.

(28) सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 42 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत

किया गया है: -

(42) वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति। -

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी भी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) जिसे अधिकार प्राप्त है इस संबंध में केंद्र सरकार, या राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी ऐसे अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान से या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए टन-नेशन में विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है, कि कोई भी मादक दवा, या मनोदैहिक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ में जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान में रखी या छिपाई गई है, -

(a) 1 ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में घुसकर तलाशी लेना;

(b) आसानी से, किसी भी दरवाजे को तोड़ें और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा दें;

(c) ऐसी दवा, पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी भी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त कर लें, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है और किसी भी दस्तावेज या अन्य लेख को जब्त कर सकता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के कमीशन का सबूत; और

(d) हिरासत में लें और तलाशी लें, और, यदि वह उचित समझे, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है:

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास आईसीवीसी को स्वीकार करने का कारण है कि साक्ष्य छुपाने का अवसर दिए बिना या प्रशंसक अपराधी के भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान की तलाशी ले सकता है। अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने के बाद सूर्य अस्त और सूर्योदय हुआ।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके परंतुक के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो उसे तुरंत उसकी एक प्रति अपने निकटतम वरिष्ठ को भेजनी होगी।

(29) इस आसानी में अफ़ीम की बरामदगी किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी से नहीं की गई. 'डायल केवल अपीलकर्ता द्वारा अपने दाहिने हाथ में रखे गए बैग से बनाया गया था। संदेह के आधार पर, अपीलकर्ता को PW4 द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसे संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेने का पूरा अधिकार था।

11 सी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना अपीलकर्ता द्वारा अपने दाहिने हाथ में ले जाए जा रहे बैग को बरामद करने में पूरी तरह से सक्षम था।

(30) अपीलकर्ता से अफीम की बरामदगी के बाद, पीडब्लू4 ने रुका एक्स.पीबी को पुलिस स्टेशन भेजा, जहां फॉर्मा] एफआईआर एक्स.पीबी/1 रमेश वार दत्त, एसआई द्वारा दर्ज की गई थी। बाद में, कानून के अनुसार, एफआईआर एक्स.पीबी/1 की प्रतियां पीडब्लू4 के वरिष्ठ/उच्च पुलिस अधिकारियों और इलाक़ा मजिस्ट्रेट को भी भेज दी गईं। यह सब PW3 और PW4 के बयानों से बना है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन अपीलकर्ता से अफीम की बरामदगी के समय पीडब्लू4 द्वारा किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए इस विवाद में कोई बल नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है।

(31) अब यह देखना होगा कि अधिनियम की धारा 52 का अनुपालन किया गया था या नहीं। अधिनियम की धारा 52 को अंडरसीआर के रूप में पढ़ा जाता है: -

<u>52. गिरफ्तार व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं का निपटान। -</u>

(1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक

व्यक्ति और जब्त किए गए सामान को उस मजिस्ट्रेट को अनावश्यक देरी के बिना भेजा जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।

(3) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 की उप-धारा (2) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त किए गए सामान को अनावश्यक देरी के बिना अग्रेषित किया जाएगा-

(a) निकटतम पुलिस स्टेशन का अधिकारी-प्रभारी, या

(b) अधिकारी को धारा 53 के तहत अधिकार दिया गया है।

(32) 'वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत कोई व्यक्ति या वस्तु भेजी जाती है, सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ, ऐसे व्यक्ति या वस्तु के कानून के अनुसार निपटान के लिए आवश्यक उपाय करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के आधार पर नहीं है, तो उसकी आगे की हिरासत अमान्य या गैरकानूनी हो सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी प्रारंभिक गिरफ्तारी ही अवैध हो जाती है। पीडब्लू 3 के साक्ष्य में यह स्पष्ट है और पीडब्लू4 कि अफीम की बरामदगी के बाद, गिरफ्तारी के आधार प्रतिवादी को सूचित कर दिए गए थे, इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 52 का अनुपालन नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया विवाद। इस संबंध में, योग्यता से रहित होने के कारण, इसे निरस्त किया जाता है।

(33) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पीडब्लू 5 रमेश चंद्रा पुलिस पार्टी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और अपनी उपस्थिति में अपीलकर्ता से अफीम की कथित बरामदगी से इनकार किया। यह बयान उचित रूप से विद्वान ट्रायल कोर्ट के दिमाग में अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करने का विचार नहीं रखता था। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पीडब्लू 5 रमेश चंदर पर उचित रूप से भरोसा नहीं किया गया था, संभवतः, अपीलकर्ता ने उस पर जीत हासिल कर ली होती।

(34) जब पीडब्लू 3 और पी डब्लू 4 के पास इस आशय का सर्वसम्मत साक्ष्य है कि अपीलकर्ता के पास से 4 किलोग्राम ओपियम से भरा एक बैग बरामद किया गया था और जब इन गवाहों को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तलाशी जिरह के अधीन किया गया था और लंबे समय तक जिरह से नाम के लायक कुछ भी पता नहीं चल सका, जिससे संभवतः उनकी गवाही पर कोई असर पड़ सकता था, अभियोजन की आसानी को केवल पीडब्लू5 रमेश चंदर की गवाही के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था, जिन्होंने कहा था कि अपीलकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। उसकी उपस्थिति.

(35) PW3 की गवाही को PW3 और PW4 की गवाही पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, जिन पर वसूली के दिन से पहले अपीलकर्ता के प्रति कोई दुश्मनी या शत्रुता रखने का आरोप नहीं है।

(36) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्वतंत्र गवाह आम तौर पर अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देने से बचते हैं, क्योंकि वे इस तथ्य से डरते हैं कि अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देने से उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफल रहे, क्योंकि PW5 ने रिकवरी मेमो Lx.PA पर हस्ताक्षर किए, जबकि वह खाली था। वह कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था. इसलिए, इसकी आवश्यकता नहीं थी

पुलिसकर्मी के कहने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। 1 तो, यदि उसने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, तो उसे PW3 और PW4 के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए थी कि वह कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करना भूल गया है। अब, उसे यह दावा करने से रोका जाएगा कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के डर या शत्रुता के कारण, उसने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर लेने के लिए उनके खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की। इस प्रकार, वह उस मामले पर चुप रहे, जिस पर उन्हें कोरे कागजों पर अपने हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के उच्च अधिकारियों को सूचित करके तत्परता से काम करना चाहिए था। इस मामले में मेरी चुप्पी, जहां उन्हें तत्परता से काम करना चाहिए था, वास्तव में पेचीदा है और यह माना जाना चाहिए कि उन्हें अपीलकर्ता ने जीत लिया था, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया था, जिनके बयानों को गैर-आधिकारिक बयान के बराबर माना जाना चाहिए। गवाह. सड़क पर घूम रहे किसी व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

(37) ***दर्शन खान*** बनाम ***पंजाब राज्य (4) में यह*** माना गया था कि सजा आधिकारिक गवाहों की गवाही पर आधारित हो सकती है। जब PW3 और PW4, जिनकी उपस्थिति में अपीलकर्ता से अफीम की बरामदगी की गई थी, पर बाद वाले के खिलाफ कोई शत्रुता या शत्रुता होने का आरोप नहीं लगाया गया था, तो उनकी गवाही को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज नहीं किया गया था, इस प्रकार, उन्होंने सही ढंग से उस पर भरोसा किया, अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराने के लिए।

(38) ***रूप सिंह*** बनाम ***पंजाब राज्य (5)*** के मामले में , इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि स्वतंत्र गवाह को जीत लिया गया और छोड़ दिया गया; मामला सरकारी गवाहों पर आधारित था; इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि पुलिस अधिकारी दुर्भावनापूर्ण था और मामले को झूठा फंसाने में रुचि रखता था; पुलिस अधिकारियों की गवाही को उनकी विस्तृत जिरह

में खारिज नहीं किया जा सका। इस फैसले के मद्देनजर, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता।

(39) प्रकरण में अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन भी कराया गया। पुलिस स्टेशन लौटने पर पीडब्लू4 ने इंस्पेक्टर पीडब्लू6 कैदारनाथ राथेक, जो कि पुलिस स्टेशन सिटी पानीपत में एसएचओ के रूप में कार्यरत थे, के समक्ष मामले की संपत्ति पेश की। उनके बयान के अनुसार,

(4) 1999(1) आरसीआर (सीआरएल) 269
(5) 1996(1) आरसीआर (सीआरएल.) 146

उन्होंने अपीलकर्ता और अन्य सभी से मामले की जांच का सत्यापन किया और पार्सल पर केएसआर छाप वाली अपनी मुहर लगाई और इन पार्सल को स्केल करने के बाद, उन्होंने उन्हें एमआई आईसी के पास सही हालत में जमा कर दिया। जिरह के दौरान इस गवाह के साक्ष्य को खंडित नहीं किया जा सका। तो, इन परिस्थितियों में, यह मानना होगा कि अधिनियम की धारा 55 का भी अनुपालन किया गया था।

(40) विचारण के दौरान मामले की संपत्ति को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पार्सल Ex.P2 में आसानी का विवरण नहीं था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लास्टिक बैग Ex.Pl में मामले का विवरण न हो। पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 पर कोई जिरह नहीं हुई है, मुकदमे के दौरान जो संपत्ति पेश की गई थी वह किसी अन्य आसानी से संबंधित थी। PW6 के बयान के दौरान अफ़ीम Ex.P2 युक्त टिन बॉक्स भी पेश किया गया था।

(41) विश्लेषण के लिए नमूना ईएसई को भेजने में 11 दिनों की देरी हुई है। यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, क्योंकि उस देरी का उपयोग नमूना पार्सल और आसानी संपत्ति को तैयार करने के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि तथ्य यह है कि आसानी संपत्ति पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 6 के कब्जे में रही। जिरह के दौरान उनकी गवाही को खंडित नहीं किया जा सका। यह उनका प्रमाण है कि, जब तक नमूना पार्सल और सहज संपत्ति उनके कब्जे में रही, तब तक किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि ईएसएल के पास जमा होने तक जांच के दौरान नमूना पार्सल के साथ कभी छेड़छाड़ की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में एक्स.पीडी ने कहा था कि नमूना पार्सल की सामग्री अफीम थी।

(42) इन परिस्थितियों में, यह इस प्रकार है कि अपीलकर्ता को 17.09.1989 को सिटी

पानीपत के क्षेत्र में बिना किसी लाइसेंस या परमिट के 4 किलोग्राम ओपियम के कब्जे में पाया गया था। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उसे उचित रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जो कि किसी भी अवैधता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

जे. *जैन*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा